Level Vigilance and Monitoring Committees and Employment Assurance Scheme Committees at District and Block Level. Such Committees review, monitor and supervise the implementation and execution of the various programmes of this Ministry. Further, utilization of funds is also monitored by obtaining regular Monthly Progress Report from States/ District Rural Development Agencies. In addition to this, utilization certificate and audit reportes duly certified by Chartered Accountant are also taken into account while releasing the funds to the DRDAs. Instructions have also been issued for not depositing the DRDA funds in the State Treasury. Whenever any complaint regarding implementation of programmes is received in the Ministry, appropriate action is taken.

Unemployment allowance in rural areas

2386. SHRI S.S. SURJEWALA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the total number of educated unemployed matriculation and above in the rural areas of the contry, State-wise figures separately, upto the 31st March, 1998;

(b) whether Government have provided a facility which may help them starting self employment careers; if so, the details of the schemes; and

(c) whether any proposal is under consideration of Government to provide unemployment allowance to these educated youth; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) The latest estimates for employment and unemployment are available only upto 1993-94, which are based on 50th round Survey of NSSO. The number of educated unemployed matriculation and above, as per these estimates, in Rural Areas State-wise are given in the Statement. (*See* below)

(b) Ministry of Rural Areas & Employment is implementing various programmes namely (i) Integrated Rural Development Programme (IRDP), (ii) Training of Rural Youth for Self Employment (TRYSEM), (iii) Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA) for providing self employment to rural poor including educated unemployed matriculation and above. In addition, Department of Small Scale Agro & Rural Industries is implementing Prime Minister Rozgar Yojana (PMRY) for providing self employment to educated unemployed youth in the country.

(c) No such proposal is under consideration of this Ministry.

Statement

State-wise estimates for Matriculates & above educated unemployed (in Rural India) (In thousands)

State/UT	Educated Unemployed
1. Andhra Pradesh	122
2. Arunachal Pradesh	2
3. Assam	297
4. Bihar	312
5. Goa	17
6. Gujarat	77
7. Haryana	79
8. Himachal Pradesh	95
9. Jammu & Kashmir	15
10. Karnataka	130
11. Kerala	482
12. Madhya Pradesh	95
13. Maharashtra	166
14. Manipur	7
15. Meghalaya	0
16. Mizoram	2
17. Nagaland	2
18. Orissa	15
19. Punjab	56
20. Rajasthan	30
21. Sikkim	1
22. Tamil Nadu	266

23. Tripura	18
24. Uttar Pradesh	243
25. West Bengal	249
26. A&N Islands	3
27. Chandigarh	1
28. Dadra & Nagar Haveli	0
29. Daman & Diu	0
30. Delhi	0
31. Lakshadweep	0
32. Pondicherry	2
ALL	2870

Source: Planning Commission (LEM Division) on the basis of 50th round survey of NSSO.

ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण

2387. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 87% ग्रामीण क्षेत्र का अब तक विद्युतीकरण किया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अब तक केवल 31% घरों को ही बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोग इसलिए कम होता है क्योंकि वहां बिजली कम मात्रा में उपलब्ध होती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल कितने परिवारों को बिजली मुहैया करायी जाने का लक्ष्य है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटिल): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोका जाना

2388. श्री नागमणि: क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोजगार के अवसरों और जीवनयापन के अन्य साधनों की वजह से लोग बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्र की आबादी सहित शहरी क्षेत्रों में गए लोगों की संख्या क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के और अवसर प्रदान किए जाएंगे जिससे इस प्रवृत्ति को विपरीत मोड़ दिया जा सके; और

(घ) गांवों से शहरों की ओर लोगों के इस तरह के पलायन को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटिल): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार रोजगार या व्यवसाय की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या 104 मिलियन थी और कुल ग्रामीण आबादी 628.69 मिलियन थी।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए कई कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। अर्थात् (क) जवाहर रोजगार योजना (ख) सुनिश्चित रोजगार योजना (ग) दस लाख कुओं की योजना (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ङ) ट्राइसेम (च) डवाकरा और (छ) ग्रामीण कारीगरों के उन्नत औजार किटों की आपूर्ति।

ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीकरण

2389. **श्री नागमणि: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीकरण करने का विचार रखती है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्र के कुल अकुशल, कुशल, अशिक्षित और शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की जा चुकी है/की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका को निर्धारित किया गया है/किया जा रहा है; और

(ङ) क्या इस कार्यक्रम में वित्तीय संस्थानों की भूमिका भी निर्धारित की गयी है?